मेहता समिति की रिपोर्ट

*७०२. **श्री नवाबसिंह चौहान :** क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी ऋण के सम्बन्ध में सरकार ने जो मेहता समिति नियुक्त की थी क्या उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है, और यदि हां, तो क्या सरकार इस रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ; और

(ख) क्या सरकार ने रिपोर्ट पर विचार कर लिया है और यदि हां तो इस की किन किन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है ?

†[MEHTA COMMITTEE REPORT

*702. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION be pleased to state:

(a) whether the Mehta Committee, which was appointed by Government in connection with co-operative credit, has submitted its report; and if so, whether Government will lay a copy of the report on the Table of the House; and

(b) whether Government have considered the report and if so, which of its recommendations have been accepted?]

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री के संसदीय सचिव (श्री एस० डी० मिश्र) : (क) जी हां

समिति का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जाता है ।

(ख) सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

†[THE PARLIAMENTARY SECRETARY TO THE MINISTER OF COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI S. D. MISRA):

(a) Yes, Sir. The report of the Committee is laid on the Table of the House.

(b) The recommendations are under consideration.]

श्री नवाबसिंह चौहान : कब तक आशा करें कि इन रिकमेंडेशंस के ऊपर विचार पूरा हो जायगा और ये अमल में आने लगेंगी ? और क्या विचार करने से पहले गवर्नमेंट ने कुछ चीजों पर अमल करना अच्छा समझा है ? अगर ऐसा है, तो वे क्या चीजें हैं ?

SHRI S. D. MISRA: Sir, final decisions will be taken within some days only and then they will be communicated to the State Governments.

श्री नवाबसिंह चौहान : सरकार इस वक्त कितना क्रेडिट दे रही है और इस कमेटी ने इस संम्बन्ध में क्या सिफारिश की है क्या सोसाइटीज़ को सरकार का इरादा सीधे क्रेडिट देने का है या रिज़र्व बैंक के ज़रिये ?

SHRI S. D. MISRA: Sir, at the end of 1960-61, the agriculturists will receive Rs. 190 crores of credit from the co-operative societies. This Committee has not set any limit but the Working Group which was formed has suggested that by the end of the Third Plan Rs. 500 to Rs. 600 crores of credit should be given annually. Regarding the share participation it will be indirect through the central banks and not direct by the Government.

ACQUISITION OF LAND FOR THE GOVERNMENT SERVANTS' HOUSE BUILDING CO-OPERATIVE SOCIETIES IN DELHI/NEW DELHI

*703. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of HEALTH be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to acquire land for the Government Servants' House

†[ ] English translation.